अहमदाबाद नगर निगम

बनाम

जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 5360-5363)

16 दिसंबर, 2016

[रंजन गोगोई और प्रफुल्ल सी. पंत, जे.जे.]

गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949-उपधारा 145 ए, 127(1), 2(5), (30), (34 एए) - मोबाइल टावरों पर संपत्ति कर लगाना: मोबाइल टावर सातवीं अनुसूची शक्ति की प्रविष्टि 49 सूची II में दिखाई देने वाली भूमि और भवन के दायरे में आते हैं। सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत मोबाइल टावर पर कराधान का अधिकार राज्य विधानमंडल में निहित है, कर का भुगतान कब्जेदार द्वारा किया जाएगा, न कि भूमि और भवन के मालिक द्वारा गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, 2011 धारा 145 ए गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 - गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 - भारत का संविधान - प्रविष्टि 49, सूची II, सातवीं अनुसूची।

न्यायालय ने सभी अपीलों, रिट याचिकाओं और स्थानांतरित मामलों का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 किसी भी विधायी प्रविष्टि का अर्थ, उदाहरण "भूमि और भवनों पर कर" (सूची II की प्रविष्टि 49) को किसी विशेष विधान प्रविष्टि के लिए क़ानून में दिखाई देने वाली उन्हीं अभिव्यक्तियों की परिभाषा के संदर्भ में नहीं समझा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, हालांकि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 "भूमि" और

"भवन" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है, लेकिन परिभाषा खंड के संदर्भ में सूची II की प्रविष्टि 49 के अर्थ और दायरे को समझना अपने आप में कठिन होगा। गुजरात अधिनियम क़ानून में निहित परिभाषाएँ कभी-कभी व्यापक और व्यापक हो सकती हैं; शब्दों के स्वाभाविक अर्थ से परे या इसमें अपमानजनक प्रावधान भी हो सकते हैं। यद्यपि किसी क़ानून में परिभाषा द्वारा किसी विशेष अभिव्यक्ति को बताए गए व्यापक अर्थ को प्रभावी बनाना होगा, यदि क़ानून अन्यथा वैध पाया जाता है, तो यह वास्तव में वैधता का परीक्षण करने के संदर्भ में एक विरोधाभास होगा। इसके भीतर होने की कसौटी पर क़ानून का विधायी प्रविष्टि, क़ानून में निहित परिभाषा के संदर्भ में। [पैरा 14] [181-सी-ई]

1.2 दूसरा पहलू, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I या II या यहां तक कि सूची III में दो अलग-अलग प्रविष्टियों से संबंधित दो अलग-अलग क़ानूनों के अनुमेय संचालन से संबंधित है। इसे उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश में, यह स्वीकार करते हुए स्वीकार किया है कि भले ही एक मोबाइल टावर सूची I की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत आने वाले "टेलीग्राफ" से संबंधित उपकरण का एक हिस्सा है, फिर भी, गुजरात अधिनियम अभी भी सह- हो सकता है। भूमि और भवनों पर इतने लंबे समय तक कर लगाने के लिए एक क़ानून के रूप में अस्तित्व में है और यदि केवल मोबाइल टावर सूची II की प्रविष्टि 49 में उक्त अभिव्यक्ति "भूमि और भवन" के दायरे और दायरे में आ सकते हैं। इसलिए, संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या को नियंत्रित करने वाले मापदंडों और सिद्धांतों के सही अनुप्रयोग द्वारा सूची II की प्रविष्टि 49 के विरुद्ध दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "भूमि और भवन" के सही अर्थ का पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से किसी भी प्रविष्टि में। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत विधायी क्षेत्र। [पैरा 15][181-एफ-एच; 182-ए]

1.3 कराधान के क्षेत्र जिन पर केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए कानून बनाने में सक्षम हैं, संबंधित सूचियों में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। हालाँकि किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, यह संभव है कि किसी दिए गए स्थिति में हालांकि केंद्र और राज्य अधिनियम द्वारा लगाए गए करों के बीच कुछ समानता हो सकती है, दोनों लेवी के विषय के संबंध में सह-अस्तित्व में हो सकते हैं। भूमि से प्राप्त आय पर कर और स्वयं भूमि पर एक कर जिसमें आय या कमाई कर लगाने की दरों का आधार बनती है। भले ही यह मान लिया जाए कि सेलुलर ऑपरेटरों का यह तर्क सही है कि मोबाइल टावर "टेलीग्राफ" क्षेत्र (सूची I की प्रविष्टि 31) के अंतर्गत आते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या मोबाइल टावर सूची की प्रविष्टि 49 के दायरे में आ सकते हैं II, ऐसा कानून विधायी रूप से अक्षम होगा। [पैरा 20] [184-एफ-एच]

1.4 सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में विधायी प्रविष्टि की व्याख्या का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि उसमें शब्दों और अभिव्यक्तियों को अर्थ में समावेशी माना जाए और ऐसे अर्थ को समय के साथ समकालीन धारणाओं तक सीमित करने के बजाय सभी संभव लचीलापन दिया जाए। जब संविधान बनाया गया। संविधान, एक जैविक दस्तावेज़, को व्याख्या की ऐसी प्रक्रिया द्वारा स्वाभाविक विकास की अनुमति दी जानी चाहिए। विधायी प्रविष्टि की व्याख्या को समय की गति के साथ बढ़ना और बनाए रखना होगा। [पैरा 24] [188-बी-सी]

1.5 क़ानून के प्रावधानों के दायरे का परीक्षण करने के लिए 'भूमि' और 'भवन' शब्दों के दायरे और विस्तार को विधायी प्रविष्टि (प्रविष्टि 49 सूची II) के प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि प्रविष्टि से संबंधित क़ानून. हालाँकि, व्याख्या के उन सिद्धांतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा जिनका पालन इस न्यायालय ने

क़ानून में निहित "भूमि" और "भवन" अभिव्यक्तियों के सही अर्थ और दायरे के संबंध में अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में किया था। सामान्य क़ानून की व्याख्या के सिद्धांत संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं। [पैरा 27] [189-जी; 190-ए-बी]

1.6 संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर चर्चा एक संवैधानिक योजना का सुझाव देगी जिसमें भारतीय संघ के संघीय राज्यों को ऐसी स्थिति के बावजूद वित्तीय रूप से कमजोर बने रहना तय नहीं है जहां निस्संदेह अधिक आवंटन के कारण संघ का पलड़ा भारी है। सातवीं अनुसूची के तहत कराधान के आकर्षक विषय। गुजरात अधिनियम की संवैधानिकता पर राज्य के पक्ष में जवाब दिया जाना चाहिए। [पैरा 27] [191-ए-बी]

1.7 सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II में प्रदर्शित अभिव्यक्ति "भवन" स्थापित सिद्धांतों के मद्देनजर उक्त अभिव्यक्ति के सही और सही अर्थ का पता लगाने के लिए लागू होगी, अभिव्यक्ति के अर्थ को सीमित करना मुश्किल होगा " भवन" एक आवासीय भवन है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है या रहने के उद्देश्य से बनाई गई संरचना है। [पैरा 28] [191-सी]

1.8 2011 के संशोधन द्वारा गुजरात अधिनियम में मोबाइल टावरों के विशिष्ट समावेश से पहले भी 'मोबाइल टावरों' की स्थापना, स्थान और संचालन के मामले में निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों की नियामक शक्ति और बॉम्बे अधिनियम के तहत इस तरह का नियंत्रण। राज्य में निहित होने वाले मोबाइल टावरों पर कराधान की शक्ति को समझकर ऐसी शक्ति और नियंत्रण का उचित विस्तार प्रदान करने के लिए समय के बिंदु भी एक मूल्यवान इनपुट होंगे। सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत विधानमंडल। [पैरा 29] [191-एफ]

1.9 लेवी का माप, हालांकि कर की प्रकृति का निर्धारक नहीं हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े गए दोनों अधिनियमों के तहत, मोबाइल टावरों पर कर भूमि और भवन से प्राप्त उपज पर लगाया जाता है, जिसकी गणना भूमि और भवन के मूल्य निर्धारण के आधार पर की जाती है। इसके अलावा कर की घटना मोबाइल टॉवर में संयंत्र और मशीनरी के उपयोग पर नहीं है; बल्कि यह मोबाइल टावर के प्रयोजन के लिए भूमि या भवन के उपयोग पर है, जैसा कि हो सकता है। यह कर "ऐसे मोबाइल टावरों के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे व्यक्ति" पर लगाया गया है (गुजरात अधिनियम की धारा 145 ए) केवल यह दर्शाता है कि यह कब्जा करने वाला है, न कि भूमि और भवन का मालिक जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।. मालिक के बजाय कब्जेदार द्वारा कर का भुगतान करने की ऐसी देनदारी सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II के तहत भूमि और भवन पर देय कर का एक स्वीकृत पहलू है। [पैरा 30] [191-जी-एच; 192-ए-बी]

1.10 यदि गुजरात अधिनियम में निहित "भूमि" और "भवन" की परिभाषा को समझा जाए, तो इसका कोई कारण नहीं है, हालांकि आम बोलचाल और रोजमर्रा की जिंदगी में, एक मोबाइल टावर निश्चित रूप से एक इमारत नहीं है, यह क्यों होगा प्रविष्टि 49 सूची II के प्रयोजनों के लिए एक इमारत बनना भी बंद कर दिया जाएगा ताकि राज्य विधानमंडल को उस पर कर लगाने की शक्ति से वंचित किया जा सके। ऐसा कानून अपने स्रोत का पता संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II के प्रावधानों से लगा सकता है। [पैरा 31] [192-सी-डी]

1.11 गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द किया जाता है और बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न अपीलें; स्थानांतरित मामलों और रिट याचिकाओं का तदनुसार उत्तर दिया जाता है। (पैरा 33] [192-एफ]

सिंथेटिक्स और रसायन ढक्कन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 1 एससीसी 109: 1989 (1) पूरक एससीआर 623; शुभ वर्ष भारत ढक्कन. बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य। एआईआर 1990 एससी 781: 1989 (1) पूरक एससीआर 510; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एससीसी 201: 2004 (1) एससीआर 564; ड्रुटफ सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र. (2007) 7 एससीसी 242: 2007 (8) एससीआर 860; इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) 1 एससीसी 12: 1989 (1) पूरक एससीआर 692; जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1962 एससी 1563 : 1963 एससीआर 220; एलेल होटल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और अन्य बनाम यू.ओ.आई. (1989) 3 एससीसी 698: 1989 (2) एससीआर 880; इसके कानूनी मामले में। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 20 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 में संशोधन करने वाला विधेयक: 1964 (3) एससीआर 787; अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1975) 2 एससीसी 175: 1975 (3) एससीआर 220; गुडरिक ग्रुप लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1995) 1 सप्ल एससीसी 707: 1994 (6) पूरक एससीआर 120; अजॉय कुमार मुखर्जी बनाम बारपेटा का स्थानीय बोर्ड एआईआर 1965 एससी 1561: 1965 एससीआर 47; ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम एआईआर 1991 एससी 686: 1990 (3) पूरक एससीआर 365; आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एआईआर 1975 एससी 2037: (1975) 2 एससीसी 274: 1975 पूरक एससीआर 394- संदर्भित।

स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी पांचवां संस्करण; ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी सातवां संस्करण; पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन दूसरा संस्करण; स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी पांचवां संस्करण; ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पांचवां संस्करण; पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन दूसरा संस्करण; अंग्रेजी भाषा का कोलिन्स डिक्शनरी प्रथम संस्करण। 1979 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1989 (1) पूरक। एससीआर 623	संदर्भित	पैरा 16
1989 (1) पूरक। एससीआर 510	संदर्भित	पैरा 16
2004 (1) एससीआर 564	संदर्भित	पैरा 16
2007 (8) एससीआर 860	संदर्भित	पैरा 16
1989 (1) पूरक। एससीआर 692	संदर्भित	पैरा 16
1963 एससीआर 220	संदर्भित	पैरा 16
1989 (2) एससीआर 880	संदर्भित	पैरा 16
1964 (3) एससीआर 787	संदर्भित	पैरा 17
1975 (3) एससीआर 220	संदर्भित	पैरा 25
1994 (6) पूरक एससीआर 120	संदर्भित	पैरा 26
1965 एससीआर 47	संदर्भित	पैरा 26
1990 (3) पूरक एससीआर 365	संदर्भित	पैरा 27
1975 पूरक एससीआर 394	संदर्भित	पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5360-5363/2013।

अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के विशेष सिविल आवेदन संख्या 4084/2012, 3411/2012, 15596/2012 और 3787/2013 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24-25.04.2013 से।

साथ

2013 के सी.ए. नंबर 5364, 5365, 6385-6387, 6737-6738, 6739, 6836-6926, 7865-7894, 8114, 8115, 8116 और 8117

2014 का सी.ए. नंबर 2854-2855

2015 का सी. ए. नंबर 5348

2016 का सी.ए. नंबर 12209, 12211, 12212, 12213, 12214-12215, 12216, 12217, 12218, 12219, 12220, 12221, 12222, 12223, 12224, 12225, 12226, 12 227, 12228, 12229, 12230, 12231, 12232, 12233, 12234,12235 और 12236

2015 के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 216, 611 और 577

2015 की टी.सी. (सी) संख्या 128, 130, 129 और 131

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, प्राग पी. त्रिपाठी, प्रशांत जी देसाई, के.वी. विश्वनाथन, के. कुमार, मिहिर जोशी, गोपाल जैन, गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रीतेश कपूर, सुश्री हेमन्तिका वाही, सुश्री अगम कौर, सुश्री पूजा सिंह, मोहित पॉल, धवल नानावटी, सुश्री दीक्षा झिंगन, डी.एन. रे, लोकेश के. चौधरी, श्रीमती सुमिता रे, के.एन. राय, चिन्मय प्रदीप शर्मा, सुश्री गौरी सुब्रमण्यम, सायन रे, ईशान दास, पुनीत तनेजा, अमन गांधी, सुश्री बिंदी गिरीश दवे, सुश्री प्रिनाज़ वकील, विवेक ए. वाशी, अनुष राजन, संदीप देशमुख, नर हरि सिंह, वेंकिता सुब्रमण्यम टी.आर., पवन कुमार, आर.एन. पारीक, अजीत कुलश्रेष्ठ, संतोष सचिन, सुश्री मनाली सिंघल, अभिजात पी. मेध, दीपक

सिंह रावत, रोहित कौल, महेश अग्रवाल, सुश्री शैली भसीन, लक्ष्मीश कामथ, ऋषभ गुप्ता, राघव पांडे, अभिषेक कौशिक, ई.सी. अग्रवाल, धनंजय भास्कर, रवि रघनाथ, शमिक भट्ट, पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री धारिता मलकान, जीतेंद्र मलकान, सुश्री अरुणिमा सिंह, समीर पारेख, सुश्री रुख्मिणी एस बोबडे, अभिषेक विनोद देशमुख, सुश्री संजना रामचन्द्रन, स्टेफनी सोनवणे (मैसर्स के लिए पारेख एंड कंपनी), साहिल टैगोत्रा (मैसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए), विनय नवारे, के.बी. ग्वेन, वी.एन. रघुपति, डी.एम. नरगोलकर, सुश्री आभा आर. शर्मा, सुश्री जयश्री वाड, आशीष वाड, सुश्री प्रोमिता मजूमदार, सुश्री जया खन्ना, मैसर्स जे.एस. वाड एंड कंपनी, सुहास कदम (मैसर्स लेमैक्स लॉयर्स एंड कंपनी के लिए), विजय कुमार, सुश्री अपर्णा झा, अरविंद एस. अवहद, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अर्पित राय, सुश्री किरण भारद्वाज, एस.एस. रावत, डी.एस. माहरा, सी. जॉर्ज थॉमस, एज़ाज़ मकबूल, सुश्री बांसुरी स्वराज, सुश्री श्रेया भटनागर, रघुनाथ सेतुपति, निर्निमेश दुबे, निखिल गुलियानी, अधिवक्ता उपस्थित पार्टियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय रंजन गोगोई, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. विलंब क्षमा किया गया। सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. मामलों के इस समूह को सुविधापूर्वक चार अलग-अलग श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। पहली अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24/25.04.2013 के फैसले और आदेश से उत्पन्न अपील हैं, जिसमें गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (इसके बाद "गुजरात अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 145ए को अधिकारातीत घोषित किया गया है। संविधान और उसके आधार पर "मोबाइल टावरों" पर संपत्ति कर लगाने पर रोक लगा दी गई है। उच्च

न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, हालांकि, यह विचार किया कि एक मोबाइल टावर में केबिन जिसमें बीटीएस प्रणाली, जिसका विवरण नीचे देखा गया है, स्थित है, एक इमारत होगी और इसलिए, गुजरात के तहत कर के दायरे में आएगी। कार्यवाही करना। राज्य सरकार और विभिन्न नगर निगमों ने उच्च न्यायालय के आदेश के पहले भाग को चुनौती दी है जबकि सेल्यूलर ऑपरेटरों ने बाद के भाग को चुनौती दी है।

3. बॉम्बे हाई कोर्ट जो कुछ हद तक इसी तरह की चुनौती से जूझ रहा था, ने चुनौती के तहत दिए गए आदेश से यह विचार किया है कि मोबाइल टावरों पर संपत्ति कर लगाने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और उनमें पीड़ित रिट याचिकाकर्ताओं (सेल्यूलर ऑपरेटरों) को विकल्प समाप्त करने के विकल्प के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए। अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपाय। यह मामलों की तीसरी श्रेणी होगी। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बॉम्बे प्रांतीय नगरपालिका में निगम अधिनियम, 1949, चार्जिंग अनुभाग विशेष रूप से नहीं है। गुजरात अधिनियम की तरह मोबाइल टावरों पर कर लगाने पर विचार करें। हालाँकि, आक्षेपित लेवी इस तर्क पर लगाया गया था कि मोबाइल टावर वे इमारतें हैं जैसा अधिनियम में परिभाषित हैं। इस स्तर पर यह होना भी चाहिए। ध्यान दें कि बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 वर्ष 2011 तक गुजरात राज्य पर भी लागू था, जब गुजरात लघु शीर्षक (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा "बॉम्बे" शब्द के स्थान पर 'गुजरात' शब्द डाला गया था।

4. मामलों की चौथी और पांचवीं श्रेणियां समान मुद्दे उठाने वाली रिट याचिकाएं होंगी जिन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय से इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सेलुलर ऑपरेटरों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष

दायर की गई रिट याचिकाएं समान मुद्दों को उठाती हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं की तरह चुनौती।

5. चूंकि लंबी सुनवाई के दौरान पेश की गई विस्तृत दलीलें गुजरात अधिनियम के प्रावधानों के आसपास केंद्रित हैं, इसलिए गुजरात के मामलों को पहली बार में उठाना सुविधाजनक हो सकता है। उसमें उत्पन्न होने वाले मुद्दों का उत्तर, किसी भी तरह से, बॉम्बे मामलों के साथ-साथ स्थानांतरित मामलों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को प्रभावी ढंग से तय करेगा।

6. गुजरात अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान "भवन", "भूमि" और "मोहिल टॉवर" को परिभाषित करते हुए इस प्रकार हैं:

"धारा 2(5) "भवन" में एक घर, बाहरी घर, अस्तबल, शेड, झोपड़ी और अन्य घेरा या संरचना शामिल है, चाहे वह चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी अन्य सामग्री से बना हो, चाहे वह मानव आवास के रूप में उपयोग किया गया हो या अन्यथा, और इसमें बरामदे, स्थिर मंच, चबूतरे, दरवाजे, परिसर की दीवारों और बाड़ और इसी तरह की दीवारें भी शामिल हैं।

XXX XXX XXX XXX XXX

धारा 2(30) "भूमि" में वह भूमि शामिल है जिस पर निर्माण किया जा रहा है या जिस पर निर्माण किया गया है या पानी से ढका हुआ है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी चीज से जुड़ी हुई हैं और विधायी द्वारा बनाए गए अधिकार किसी भी सड़क पर अधिनियमन।

XXX XXX XXX XXX XXX

धारा 2(34 एए) "मोबाइल टावर" का अर्थ है दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भूमि पर या भवन या परिसर के किसी भी हिस्से पर निर्मित या स्थापित एक अस्थायी या स्थायी संरचना, उपकरण या उपकरण।"

7. गुजरात एक्ट की धारा 127(1) में चार्जिंग सेक्शन है, निम्नलिखित शर्तें:

"127. इस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर.-

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निगम निम्नलिखित कर लगाएगा, अर्थात्:-

(ए) संपत्ति कर या तो धारा 129 के तहत या धारा 141 एए के तहत।

(बी) वाहनों, नावों और जानवरों पर कर।

(सी) मोबाइल टावरों पर कर:

बशर्ते कि xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

8. गुजरात अधिनियम की धारा 129 संपत्ति कर के विभिन्न घटकों से संबंधित है जो अधिनियम के तहत लगाया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो उक्त घटक जल कर हैं; संरक्षण और सीवरेज कर; सामान्य कर 12% से कम नहीं, लेकिन दर योग्य मूल्य आदि के 30% से अधिक नहीं।

9. धारा 141 एए उस दर से संबंधित है जिस पर जल कर, संरक्षण कर और सीवरेज कर लगाया जाना है। गुजरात अधिनियम की धारा 141 बी उस दर का प्रावधान करती है जिस पर सामान्य कर लगाया जाएगा।

10. धारा 145 ए (गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा सम्मिलित) मोबाइल टावरों पर राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होने पर कर का प्रावधान करती है। मोबाइल टावरों पर

लगाया जाने वाला ऐसा कर सेवा टावरों के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे व्यक्तियों से एकत्र किया जाता है। धारा 145ए निम्नलिखित शर्तों में है:

"मोबाइल टावरों पर 145ए टैक्स.-

(1) ऐसे मोबाइल टावरों के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे व्यक्ति से मोबाइल टावरों पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं कर लगाया जाएगा।

(2) निगम साल-दर-साल, धारा 99 के अनुसार, उन दरों का निर्धारण करेगा जिन पर कर लगाया जाएगा।"

11. उपरोक्त गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा मोबाइल टावरों पर कर लगाने के समान प्रावधान गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 और गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 में भी शामिल किए गए हैं।

12. उच्च न्यायालय के समक्ष सेलुलर ऑपरेटरों की संक्षिप्त दलील यह है कि गुजरात अधिनियम की धारा 145ए के साथ पढ़ी गई धारा 127(1)(सी) विधायी रूप से अक्षम है क्योंकि मोबाइल टावर सूची II की प्रविष्टि 49 के दायरे से बाहर हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची जो निम्नलिखित शब्दों में है।

"49. भूमि और भवनों पर कर।"

13. उच्च न्यायालय ने उक्त तर्क को स्वीकार करना और उस आधार पर यह मानना उचित समझा कि गुजरात अधिनियम के तहत मोबाइल टावरों पर कर लगाना संविधान के दायरे से बाहर है, सिवाय इसके कि जहां तक केबिन में बीटीएस प्रणाली का संबंध है।

14. आरंभ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से जुड़े दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। किसी भी विधायी प्रविष्टि का अर्थ, उदाहरण के लिए "भूमि और भवनों पर कर" (सूची II की प्रविष्टि 49) को विशेष विधायी प्रविष्टि के लिए क़ानून में दिखाई देने वाली उन्हीं अभिव्यक्तियों की परिभाषा के संदर्भ में नहीं समझा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, हालांकि गुजरात अधिनियम "भूमि" और "भवन" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही माना है, परिभाषा के संदर्भ में सूची II की प्रविष्टि 49 के अर्थ और दायरे को समझना अपने आप में कठिन होगा। गुजरात अधिनियम में धाराएँ। क़ानून में निहित परिभाषाएँ कभी-कभी व्यापक और व्यापक हो सकती हैं; शब्दों के स्वाभाविक अर्थ से परे या इसमें अपमानजनक प्रावधान भी हो सकते हैं। यद्यपि किसी क़ानून में परिभाषा द्वारा किसी विशेष अभिव्यक्ति को बताए गए व्यापक अर्थ को प्रभावी बनाना होगा, यदि क़ानून अन्यथा वैध पाया जाता है, तो यह वास्तव में वैधता का परीक्षण करने के संदर्भ में एक विरोधाभास होगा। क़ानून में निहित परिभाषा के संदर्भ में, क़ानून के विधायी प्रविष्टि के अंतर्गत होने की कसौटी पर।

15. ऊपर उल्लिखित दूसरा पहलू, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I या II या यहां तक कि सूची III में दो अलग-अलग प्रविष्टियों से संबंधित दो अलग-अलग क़ानूनों के अनुमेय संचालन से संबंधित है। इसे उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश में, यह स्वीकार करते हुए स्वीकार किया है कि भले ही एक मोबाइल टावर सूची I की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत आने वाले "टेलीग्राफ" से संबंधित उपकरण का एक हिस्सा है, फिर भी, गुजरात अधिनियम अभी भी सह- हो सकता है। भूमि और भवनों पर इतने लंबे समय तक कर लगाने के लिए एक क़ानून के रूप में अस्तित्व में है और यदि केवल मोबाइल टावर सूची II की प्रविष्टि 49 में उपरोक्त अभिव्यक्तियों "भूमि और भवन" के दायरे और दायरे में आ सकते हैं। इसलिए, प्रयास सही अर्थ का पता लगाने

का होना चाहिए। सूची की प्रविष्टि 49 के सामने आने वाले भाव "भूमि और भवन"। II शासन करने वाले मापदंडों और सिद्धांतों के सही अनुप्रयोग द्वारा संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या, विशेष रूप से संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत किसी भी विधायी क्षेत्र में एक प्रविष्टि।

16. संवैधानिक व्याख्या के कुछ स्वीकृत और स्थापित सिद्धांतों पर अब ध्यान दिया जा सकता है। अबाधित उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, जिन पर ऐसे सिद्धांत टिके हुए हैं, इस संबंध में किसी भी विस्तृत विचार-विमर्श और बहस में प्रवेश करना आवश्यक नहीं होगा। मोटे तौर पर और उदाहरण के तौर पर इस न्यायालय के निर्णयों से निकाले गए कुछ सिद्धांत यहां नीचे दिए गए हैं।

(i) संविधान के प्रावधानों, विशेष रूप से विधायी प्रविष्टि की व्याख्या में, एक व्यापक, उदार और विस्तृत व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि प्रविष्टि का अर्थ हमेशा समावेशी होता है। [सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1]] (1990) 1 एससीसी 109 पैरा 67)

(ii) किसी क़ानून की व्याख्या के सिद्धांत विदेशी नहीं हैं और किसी संवैधानिक प्रावधान और/या किसी विशिष्ट विधायी प्रविष्टि की व्याख्या के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। [गुड ईयर इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [2]] एआईआर 1990 एससी 781 पैरा 17

(iii) संविधान एक जैविक दस्तावेज़ है जिसे समय के साथ बढ़ना और जीना चाहिए। [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड [3]] (2004) 10 एससीसी 201 पैरा 50

(iv) संविधान की भावना, संवैधानिक लक्ष्य; और संवैधानिक दर्शन को विधायी प्रविष्टि की व्यापक और उदार व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए। [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड[4]] (2004) 10 एससीसी 201 पैरा 31

(v) शब्दकोश का अर्थ और सामान्य बोलचाल का परीक्षण भी अपनाया जा सकता है। [ट्रुटफ सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र[5]] (2007) 7 एससीसी 242 पैरा 13

(vi) संवैधानिक प्रावधान या विधायी प्रविष्टि में शब्दों और अभिव्यक्तियों को अप्राकृतिक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए। [इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु राज्य[6]] (1990) 1 एससीसी 12 पैरा 18

(vii) यदि संवैधानिक प्रविष्टि में एक सामान्य शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि यह सभी सहायक और सहायक मामलों का विस्तार करता है जिन्हें उचित रूप से शामिल किया जा सकता है। [जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम यूपी राज्य[7] एआईआर 1962 एससी 1563 पैरा 10; एलेल होटल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और अन्य बनाम यू.ओ.आई.[8]] (1989) 3 एससीसी 698 पैरा 14

उपरोक्त सिद्धांत जो संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के रूप में मजबूती से स्थापित हैं, उन्हें मामले में आगे बढ़ते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

17. पुनः में, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 20 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, (1964 (3) एससीआर 787) की धारा 3 में संशोधन करने वाला विधेयक", इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की एक पीठ ने देखा है।

"कराधान के क्षेत्र के संबंध में न तो संघ और न ही राज्य असीमित अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इस अधिकार को राज्यों के संबंध में संघ की शक्तियों और जिम्मेदारियों

और नागरिकों के संबंध में राज्यों की शक्तियों के विचार से रोका गया है। से या संघ के संबंध में। संविधान का भाग XII वित्त से संबंधित है। शुरुआत में ही अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि "कानून के अधिकार के अलावा कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा।" उस अधिकार को तीन में पाया जाना है सातवीं अनुसूची में सूचियाँ भाग XI के प्रावधानों के अधीन हैं जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, विशेष रूप से इसका अध्याय। विधायी संबंधों और अनुच्छेद 246 के विशेष संदर्भ में विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है।"

18. अनुच्छेद 246 निम्नलिखित शब्दों में है:

(1) खंड (2) और (3) में किसी बात के बावजूद, संसद के पास सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची I में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

(2) खंड (3) में किसी बात के बावजूद, संसद और, खंड (1) के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी सातवीं अनुसूची में सूची III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। (इस संविधान में इसे "समवर्ती सूची" कहा गया है)।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास सातवीं अनुसूची में सूची II में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संविधान को "राज्य सूची" कहा जाता है)।

(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से (किसी राज्य में) शामिल नहीं होने पर किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में शामिल हो।

19. हालाँकि अनुच्छेद 246 को अक्सर संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को निर्धारित करने वाला समझा जाता है, लेकिन यह अवश्य माना जाना चाहिए कि ऐसी सर्वोच्चता, यदि कोई है, अत्यंत सीमित और बहुत सूक्ष्म है। ऐसा तब कहना होगा जब भारतीय संघ के संघीय ढांचे को संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों, अपनी-अपनी सूची यानी सूची I और सूची II में किसी भी मामले में कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। संघर्ष या अतिक्रमण को न्यायालयों द्वारा सुलझाया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफलता पर ही अनुच्छेद 246 के प्रावधान लागू होंगे। जहां तक सामान्य सूची यानी सूची III का संबंध है, संघ और राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने में किसी भी प्रतिकूलता को अनुच्छेद 254 द्वारा निपटाया जाता है जो अनुच्छेद के खंड (2) के प्रावधानों के अधीन राज्य कानून पर संसदीय कानून को प्रधानता देता है। संविधान का 254 जो फिर से एक प्रावधान के अधीन है जो कुछ हद तक संसदीय सर्वोच्चता का संकेत दे सकता है।

20. कराधान के क्षेत्र जिन पर केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभाएं संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए कानून बनाने में सक्षम हैं, संबंधित सूचियों में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। हालाँकि किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, यह संभव है कि किसी दिए गए स्थिति में हालांकि केंद्र और राज्य अधिनियम द्वारा लगाए गए करों के बीच कुछ समानता हो सकती है, दोनों लेवी के विषय के संबंध में सह-अस्तित्व में हो सकते हैं। भूमि से प्राप्त आय पर कर और स्वयं भूमि पर एक कर जिसमें आय या कमाई कर लगाने की दरों का आधार बनती है, ऐसा एक उदाहरण है। उपरोक्त का उदाहरण केवल उन तर्कों का उत्तर देने के लिए दिया गया है जो उच्च न्यायालय द्वारा चुनौती के तहत दिए गए आदेश में व्यक्त किए गए हैं, भले ही यह मान लिया जाए कि सेलुलर ऑपरेटर यह तर्क देने में सही हैं कि मोबाइल टावर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। टेलीग्राफ" (सूची I की प्रविष्टि

31), यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि मोबाइल टावर सूची II की प्रविष्टि 49 के दायरे में आ सकते हैं, तो ऐसा कानून विधायी रूप से अक्षम होगा।

21. संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के संबंध में संवैधानिक योजना संविधान के भाग XII द्वारा निपटाई गई है। यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के समान वितरण पर विचार करती है। हालाँकि संघ और प्रत्येक संघीय इकाई के पास अपनी-अपनी समेकित निधियाँ हैं, संविधान के भाग XII के विभिन्न प्रावधानों में मिलने वाली वित्तीय व्यवस्थाएँ और समायोजन संघ और संघीय इकाइयों के बीच राजस्व के समान वितरण के प्रयास का संकेत देंगे। इकाइयाँ भले ही ऐसा राजस्व संघ द्वारा लगाए गए करों और कर्तव्यों से प्राप्त किया जा सकता है और इसके द्वारा या राज्यों की एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। केंद्र और राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जाने वाले करों से संबंधित विधायी प्रविष्टियों के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि राजस्व का बड़ा हिस्सा संघ को जाता है क्योंकि संघ संसद द्वारा लगाए जाने वाले करों की प्रकृति के कारण इसे समेकित में जमा किया जाएगा। संघ का कोष राज्यों में राजस्व शीर्ष/कराधान शक्ति का आवंटन निश्चित रूप से एक असंतुलन को दर्शाता है, जिसे, हालांकि, उपरोक्त संवैधानिक योजना द्वारा संतुलित करने की मांग की गई है, अर्थात्, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का समान वितरण, भले ही ऐसा राजस्व प्राप्त हो सकता है। संघ द्वारा लगाए गए और वसूले जाने वाले कर और शुल्क। संवैधानिक योजना के इस पहलू को, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) मामले में निर्णय के पैरा 50 में प्रतिध्वनित किया गया है, चर्चा के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए।

22. अब हम देख सकते हैं कि मोबाइल टावर क्या है और इसमें क्या-क्या होता है। तकनीकी भाषा में मोबाइल टावर को "बेस ट्रांसीवर स्टेशन" कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित से मिलकर संरचना बनाना शामिल है:

ए. फाइबर से बने इन्सुलेट पीयूएफ सामग्री से बना एक पूर्व-निर्मित आश्रय।

बी. इलेक्ट्रॉनिक पैनल।

सी. बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) और अन्य रेडियो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन उपकरण।

डी. एक डीजल जनरेटर सेट।

ई. खोखले स्टील गैल्वनाइज्ड पाइपों से बने 6 से 9 मीटर लंबाई के छह खंभे।

ऐसी संपत्तियों के मालिकों के साथ समझौते के आधार पर एक मोबाइल टावर का निर्माण या तो खाली जमीन पर या मौजूदा इमारतों की छत पर किया जाता है।

23. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि क्या ऐसे मोबाइल टावर सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II में दिखाई देने वाली भूमि और भवन के दायरे में आ सकते हैं।इसमें दिखाई देने वाली दो अभिव्यक्तियों के अर्थों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। प्रमुख न्यायिक और अंग्रेजी शब्दकोश। जहां तक दो अभिव्यक्तियों "भूमि" और "भवन" का संबंध है, विभिन्न कार्यों में व्यक्त अलग-अलग अर्थों की एक विस्तृत सूची नीचे दी गई है।

<u>भूमि</u>

स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश (पांचवें संस्करण) में परिभाषित किया गया है कि 'भूमि' या 'भूमि' का मतलब न केवल जमीन की सतह है, बल्कि कुजस इस्ट सोलम ईजस इस्ट के लिए इसके ऊपर या नीचे या इसके ऊपर या नीचे की हर चीज (सोने या चांदी

की खदानों को छोड़कर) भी है। usque ad coelum et ad inferos (Co. Litt. 4 a; Touch, 91; 2 Bl. Com. 18; लॉर्ड कोक पृथ्वी को "स्वर्ग के उपनगर" कहते हैं)।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (सातवां संस्करण) परिभाषित करता है कि "भूमि" का अर्थ एक अचल और अविनाशी त्रि-आयामी क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा, सतह के ऊपर और नीचे का स्थान और उस पर उगने वाली या स्थायी रूप से जुड़ी हुई सभी चीजें शामिल हैं। कोशकार आगे कहते हैं, "अपने कानूनी महत्व में, "भूमि' पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सतह के नीचे और ऊपर तक फैली हुई है। न ही यह ठोस पदार्थों तक ही सीमित है, बल्कि अपनी सीमा के भीतर गैसों और तरल पदार्थों जैसी चीज़ों को भी शामिल कर सकता है। स्थान घेरने वाले भौतिक पदार्थ के द्रव्यमान की तर्ज पर "भूमि" की परिभाषा भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भूमि का मालिक उस भौतिक पदार्थ का कुछ या पूरा हिस्सा हटा सकता है, फिर भी उस स्थान को अपनी 'भूमि' के हिस्से के रूप में बनाए रख सकता है। वह बाकी है. अंततः, एक न्यायिक अवधारणा के रूप में, "भूमि" केवल त्रि-आयामी अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है, इसकी स्थिति पृथ्वी की सतह के संदर्भ में स्थित प्राकृतिक या काल्पनिक बिंदुओं द्वारा पहचानी जाती है। "भूमि' उस स्थान की निश्चित सामग्री नहीं है, हालांकि, जैसा कि हम देखेंगे, उस स्थान का मालिक उन निश्चित सामग्रियों का मालिक हो सकता है। भूमि अचल है, संपत्ति से अलग है, जो चलने योग्य है, यह अपने में भी है कानूनी महत्व, अविनाशी। अंतरिक्ष की सामग्री को भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है या उपभोग किया जा सकता है, लेकिन स्वयं अंतरिक्ष, और इसलिए 'भूमि', अपरिवर्तनीय बनी हुई है।" पीटर बट, भूमि कानून 9 (दूसरा संस्करण, 1988)।

पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन (द्वितीय संस्करण) देखता है कि "भूमि" शब्द एक व्यापक शब्द है, जिसमें खड़े पेड़, इमारतें, बाड़, पत्थर और पानी, साथ ही वह

पृथ्वी भी शामिल है जिस पर हम खड़े हैं। खड़े पेड़ों को उस भूमि का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए जिसमें उनकी जड़ें हैं और जहां से वे अपना समर्थन प्राप्त करते हैं। 'भूमि' शब्द, सामान्य कानूनी अर्थ में, एक निश्चित और स्थायी प्रकृति की हर चीज़ को समझता है और इसलिए बढ़ते पेड़ों को शामिल करता है। 48 सभी 498 95 आईसी 150-24 एएलजे 583=1926 सभी 689।

इमारत

स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश (पांचवें संस्करण) का मानना है कि एक "इमारत" क्या है, यह हमेशा डिग्री और परिस्थितियों का प्रश्न होना चाहिए: इसका "सामान्य और सामान्य अर्थ है, ईंट या पत्थर के काम का एक ब्लॉक, जो छत से ढका हुआ है" (ईशर के अनुसार) एम.आर.. मोइर बनाम विलियम्स [1892] 1 क्यू.बी. 264)। 'बिल्डिंग' शब्द के सामान्य और प्राकृतिक अर्थ में वह कपड़ा और जमीन शामिल है जिस पर यह खड़ा है (वैंकूवर द्वीप के विक्टोरिया सिटी बिशप [1921] ए.सी. 384, पृष्ठ पर 390)।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (पांचवां संस्करण) का मानना है कि "बिल्डिंग" निवास, आश्रय, भंडारण, व्यापार, निर्माण, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा और इसी तरह की चीज़ों के लिए डिज़ाइन की गई संरचना है। 'इमारत' भी एक संरचना या इमारत है जो अपनी दीवारों के भीतर एक जगह घेरती है और आमतौर पर, लेकिन जरूरी नहीं कि छत से ढकी हो।

पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन (द्वितीय संस्करण) में कहा गया है कि 'इमारत' एक घर, आउट-हाउस, गैरेज या कोई अन्य संरचना है जिसे उस जमीन के बिना खड़ा नहीं किया जा सकता जिस पर वह खड़ा है; 'इमारत' शब्द में वह कपड़ा, जिससे यह बना है, वह जमीन जिस पर इसकी दीवारें खड़ी हैं और उन दीवारों के भीतर की जमीन शामिल है। (प्रति डी.जी गौस एंड कंपनी बनाम केरल राज्य, एआईआर 1980 एससी

271 [केरल बिल्डिंग टैक्स एक्ट (1975) एस. 2(3)])

<u>भूमि एवं भवन का शब्दकोशीय अर्थ</u>

'इमारत' एक ऐसी चीज़ है जिसमें छत और दीवारें होती हैं, जैसे घर या फ़ैक्टरी। (कोलिन्स डिक्शनरी ऑफ़ द इंग्लिश लैंग्वेज, प्रथम संस्करण, 1979)

'भूमि' का तात्पर्य पृथ्वी की सतह के ठोस भाग से है, जो समुद्र, झीलों आदि से भिन्न है। (अंग्रेजी भाषा का कोलिन्स डिक्शनरी, प्रथम संस्करण, 1979)।

अन्य सभी अंग्रेजी शब्दकोश कमोबेश इसी तरह का अर्थ व्यक्त करते हैं, अर्थात्, जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है - मानव उपयोग और आवास के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बंद स्थान।

24. सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में विधायी प्रविष्टि की व्याख्या का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि उसमें शब्दों और अभिव्यक्तियों को अर्थ में समावेशी माना जाए और ऐसे अर्थ को समकालीन धारणाओं तक सीमित करने के बजाय सभी संभव लचीलापन दिया जाए। वह समय जब संविधान बनाया गया था। संविधान, एक जैविक दस्तावेज़, को व्याख्या की ऐसी प्रक्रिया द्वारा स्वाभाविक विकास की अनुमति दी जानी चाहिए। विधायी प्रविष्टि की व्याख्या को समय की गति के साथ बढ़ना और बनाए रखना होगा।

25. अब हम देख सकते हैं कि न्यायिक राय ने इस प्रश्न से कैसे निपटा है।

अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1975) 2 एससीसी 175 में इस न्यायालय के पास उसी अधिनियम के प्रावधानों (जैसा कि बॉम्बे पर लागू होता है) के संदर्भ में प्रविष्टि 49 सूची II में निहित प्रावधानों के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर था। इस तरह से पर्याप्त रोशनी और स्पष्टीकरण

प्रवाहित होता है विचार जो रिपोर्ट के पैरा 44 में उपलब्ध है जिसे नीचे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है।

> "44. याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से श्री तारकुंडे ने आग्रह किया है कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 49 के तहत, राज्य विधानमंडल को भूमि और भवनों पर करों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रस्तुत किया गया है उपरोक्त प्रविष्टि के तहत राज्य विधानमंडल के पास भूमिगत आपूर्ति लाइनों के कब्जे वाले क्षेत्र के संबंध में कर लगाने के लिए कानून बनाने की कोई क्षमता नहीं है। इकार्नड काउंसिल के अनुसार, "भूमि" शब्द भूमि की सतह को दर्शाता है, न कि भूमिगत स्तर। हम उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सूची II की प्रविष्टि 49 भूमि और इमारतों या दोनों पर इकाइयों के रूप में कर लगाने पर विचार करती है। ऐसा कर सीधे भूमि और इमारतों पर लगाया जाता है और इसका एक निश्चित संबंध होता है। धारा 129 इमारतों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने का प्रावधान करती है। धारा 139 केवल उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उस कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। "भूमि" शब्द में न केवल पृथ्वी का चेहरा शामिल है, बल्कि इसके अंतर्गत आने वाली हर चीज शामिल है। या इसके ऊपर, और इसके कानूनी अर्थ में अनिश्चित सीमा तक ऊपर और नीचे की ओर है, जो कहावत को जन्म देता है, क्यूजस इस्ट सोलम ईजस इसका उपयोग कोएलम के लिए किया जा सकता है (देखें पृष्ठ 163, 73 कॉर्पस ज्यूरिस सेकेंडम)। ब्रूम के लीगल मैक्सिम्स के अनुसार, 10 वां संस्करण, पृ. 259, भूमि का कानूनी

अर्थ न केवल अनिश्चित सीमा तक ऊपर की ओर है, बल्कि कानून में इसका विस्तार नीचे की ओर भी है, ताकि सामान्य कानून द्वारा जो कुछ भी सतह और पृथ्वी के केंद्र के बीच एक सीधी रेखा में है वह जमीन के मालिक का हो। सतह (केवल सतह ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के केंद्र से लेकर आकाश तक की सारी भूमि) और इसलिए "भूमि" शब्द, जिसका नामकरण सामान्यीकरण है, में न केवल पृथ्वी का चेहरा, बल्कि इसके नीचे की हर चीज शामिल है या इसके ऊपर।"

26. गुडरिक ग्रुप लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1995) सपोर्ट एससीसी 707) में वजन के आधार पर हरी चाय (पत्तियों) पर लगाए गए उपकर को भूमि पर कर अभिनिर्धारित किया गया, न कि उपज पर अजॉय कुमार मुखर्जी बनाम बारपेटा के स्थानीय बोर्ड (एआईआर 1965 एससी 1561) मामले में पहले के फैसले में बाजार पर कर लगाने का निर्णय लिया गया था। यह अनिवार्य रूप से भूमि पर एक लेवी है और इसलिए, प्रविष्टि 49 सूची II द्वारा अधिकृत है, हालांकि लेवी केवल उन दिनों पर लगाई गई थी जब बाजार अभिनिर्धारित किया गया था। इस न्यायालय ने, अजॉय कुमार मुखर्जी (सुप्रा) में अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया था कि,

"इस प्रकार, यह इस प्रकार है कि भूमि का वार्षिक मूल्य, जिसे निश्चित रूप से कर लगाने में ध्यान में रखा जा सकता है, सूची II की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर उस पर कर लगाने में भूमि के उपयोग को ध्यान में रखा जा सकता है। इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए कर आवश्यक रूप से उस उपयोग पर निर्भर करेगा जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इस स्थापित प्रस्ताव के आलोक में

हमें अधिनियम की धारा 62 की योजना की जांच करनी होगी, जो चुनौती के तहत कर लगाता है।"

27. ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम में बॉम्बे (एआईआर 1991 एससी 686) प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 3 (आर) और 3 (एस) में भूमि' और 'भवन' की परिभाषाओं को इस न्यायालय द्वारा निपटाया और विचार किया गया और एक व्यापक और व्यापक उक्त भावों का अर्थ इष्ट था। हालाँकि, हमने पहले जो संकेत दिया है, उसके मद्देनजर हम रिपोर्ट के उक्त भाग को छोड़ सकते हैं, अर्थात्, क़ानून के प्रावधानों के दायरे का परीक्षण करने के लिए "भूमि" और "शब्दों का दायरा और विस्तार" भवन" को विधायी प्रविष्टि (प्रविष्टि 49 सूची II) के प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। प्रविष्टि से संबंधित क़ानून नहीं। हालाँकि, व्याख्या के उन सिद्धांतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा जिनका पालन इस न्यायालय ने क़ानून में निहित "भूमि" और "भवन" अभिव्यक्तियों के सही अर्थ और दायरे के संबंध में अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में किया था। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि सामान्य क़ानून की व्याख्या के सिद्धांत संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं। ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम (सुप्रा) में रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 पर अब ध्यान दिया जा सकता है।

18. सपा में. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981 पूरक एससीसी 87) में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने माना कि यह धारा पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिनियमित की गई थी, लेकिन इसका अर्थ और

सामग्री स्थिर नहीं रह सकती। प्रत्येक वैधानिक प्रावधान की व्याख्या को बदलती अवधारणाओं और मूल्यों के साथ तालमेल रखना चाहिए और इसे, जिस हद तक इसकी भाषा अनुमति देती है या बल्कि निषिद्ध नहीं करती है, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से समायोजन करना चाहिए ताकि तेजी से बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। जो तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वैधानिक प्रावधान की भाषा विचारों और अवधारणाओं का एक स्थिर वाहन नहीं है और जैसे-जैसे विचार और अवधारणाएं बदलती हैं, जैसा कि हमारे जैसे किसी भी देश में समतावादी मूल्यों और आक्रामक विकासात्मक रणनीतियों पर आधारित लोकतांत्रिक संरचना की स्थापना के साथ होना तय है, इसलिए वैधानिक प्रावधान के अर्थ और सामग्री में बदलाव होना चाहिए। यह प्राथमिक बात है कि कानून शून्य में काम नहीं करता है। यह कोई प्राचीन वस्तु नहीं है जिसे हटा दिया जाए, झाड़ा जाए, सराहा जाए और वापस शेल्फ पर रख दिया जाए, बल्कि यह परस्पर विरोधी हितों के बीच टकराव के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्षों और तनावों को समायोजित करने के उद्देश्य से समाज द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली उपकरण है। इसलिए, इसका उद्देश्य एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना है और इसकी व्याख्या उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सेटिंग को ध्यान में रखे बिना नहीं की जा सकती है जिसमें इसे संचालित करने का इरादा है। यहीं पर एक न्यायाधीश को रचनात्मक कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। उसे विधायिका द्वारा प्रदान किए गए सूखे ढांचे में मांस और रक्त डालना होगा और गतिशील व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से इसे एक ऐसे अर्थ के साथ निवेश करना होगा जो कानून को प्रचलित अवधारणाओं और मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा और इसे न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन बना देगा।

संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर पहले हुई चर्चाओं में एक संवैधानिक योजना का सुझाव दिया जाएगा, जिसमें भारतीय संघ के संघीय राज्यों को ऐसी स्थिति

के बावजूद वित्तीय रूप से कमजोर बने रहना तय नहीं है, जहां निस्संदेह आवंटन के मामले में संघ का पलड़ा भारी है। सातवीं अनुसूची के तहत कराधान के अधिक आकर्षक विषय। उपरोक्त आलोक में गुजरात अधिनियम की संवैधानिकता पर राज्य के पक्ष में उत्तर दिया जाना चाहिए।

28. सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II में प्रदर्शित अभिव्यक्ति "भवन" की बात करें तो स्थापित सिद्धांतों के मद्देनजर, जो उक्त अभिव्यक्ति के सही और सही अर्थ का पता लगाने के लिए लागू होंगे, अर्थ को सीमित करना मुश्किल होगा। "भवन" शब्द का अर्थ आवासीय भवन है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है या रहने के उद्देश्य से बनाई गई संरचना। आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एआईआर 1975 एससी 2037-(1975) 2 एससीसी 274) के मामले में, एक फैक्ट्री वाले भवन पर कर को भवन पर कर के रूप में समझा गया है, न कि कारखाने या उसके संयंत्र और मशीनरी पर। 'बिल्डिंग' जैसा एक सामान्य शब्द इसे सभी सहायक और सहायक मामलों तक उचित रूप से विस्तारित माना जाना चाहिए और भवन और मशीनरी पर कर लगाने के अर्थ को पकड़ने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया सामान्य बोलचाल का परीक्षण व्याख्या के स्थापित और स्वीकृत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सही प्रतीत नहीं होता है। एक संवैधानिक प्रावधान या एक विधायी प्रविष्टि का। यदि संवैधानिक दस्तावेज को तेजी से विकसित हो रही दुनिया की चुनौतियों का सामना करना है और चुनौती की नई सीमाएं और लगातार बदलती सामाजिक व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना है, तो पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण के बजाय एक गतिशील दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

29. 2011 के संशोधन द्वारा गुजरात अधिनियम में मोबाइल टावरों के विशिष्ट समावेश से पहले भी "मोबाइल टावरों" की स्थापना, स्थान और संचालन के मामले में

निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों की नियामक शक्ति और बॉम्बे अधिनियम के तहत इस तरह का नियंत्रण सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत राज्य विधानमंडल में निहित किए जाने वाले मोबाइल टावरों पर कराधान की शक्ति को समझकर ऐसी शक्ति और नियंत्रण का उचित विस्तार प्रदान करने के लिए समय के सभी बिंदु भी एक मूल्यवान इनपुट होंगे।

30. लेवी का माप, हालांकि कर की प्रकृति का निर्धारक नहीं हो सकता है, गुडरिक (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आलोक में इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े गए दोनों अधिनियमों के तहत, मोबाइल टावरों पर कर लगाया जाता है। भूमि और भवन से उपज की गणना भूमि और भवन के मूल्यांकित मूल्य के आधार पर की जाती है। इसके अलावा कर की घटना मोबाइल टावर में संयंत्र और मशीनरी के उपयोग पर नहीं है, बल्कि यह मोबाइल टावर के उद्देश्य के लिए भूमि या भवन के उपयोग पर है। यह कर "ऐसे मोबाइल टावरों के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे व्यक्ति" पर लगाया गया है (गुजरात अधिनियम की धारा 145 ए) केवल यह दर्शाता है कि यह कब्जा करने वाला है, न कि भूमि और भवन का मालिक जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।. मालिक के बजाय कब्जेदार द्वारा कर का भुगतान करने की ऐसी देनदारी सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II के तहत भूमि और भवन पर देय कर का एक स्वीकृत पहलू है।

31. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यदि गुजरात अधिनियम में निहित "भूमि" और "भवन" की परिभाषा को समझना है, तो हमें इसका कोई कारण नहीं मिलता है, हालांकि आम बोलचाल में और रोजमर्रा की जिंदगी में, एक मोबाइल टावर निश्चित रूप से एक इमारत नहीं है, यह प्रविष्टि 49 सूची II के प्रयोजनों के लिए एक इमारत भी

नहीं रह जाएगा ताकि राज्य विधानमंडल को उस पर कर लगाने की शक्ति से वंचित किया जा सके। ऐसा कानून अपने स्रोत का पता संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II के प्रावधानों से लगा सकता है।

32. हालाँकि इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई अन्य निर्णय हमारे सामने रखे गए हैं, हम उक्त निर्णयों में दिए गए प्रस्तावों का उल्लेख करना या उन पर किसी भी चर्चा में शामिल होना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि सभी में व्यक्त विचार हैं। उपरोक्त मामले "भूमि" और "भवन" अभिव्यक्तियों के अर्थ से संबंधित हैं जैसा कि प्रश्न में क़ानून के परिभाषा खंड में दिखाई देता है।

33. इसलिए, हम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द करते हैं और बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश, स्थानांतरित मामलों और रिट याचिकाओं से उत्पन्न अपीलों का तदनुसार जवाब देते हैं। हालाँकि, हम इसे खुला छोड़ते हैं, जहाँ तक बॉम्बे मामलों में सेलुलर ऑपरेटरों का सवाल है, कर के मूल्यांकन/मांग और उसकी मात्रा के पूर्वव्यापी संचालन के संबंध में मुद्दे को उचित मंच के समक्ष उठाने के लिए, यदि ऐसी सलाह दी जाती है। परिणामस्वरूप, और उपरोक्त के आलोक में सभी अपीलों, रिट याचिकाओं और स्थानांतरित मामलों का निपटारा किया जाता है।

निधि जैन

मामलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।